

(c) कठोरों के प्रयोग में समानता :-

कानूनी समानता की अधिकारी के साथ सभी प्राक्तियों के कठोर भी एक समान होंगे। जन्म, वंश, धर्म या संपत्ति आदि के आधार पर न तो किसी को विशेष सुविधाएं प्राप्त होंगी और न उनके कठोर ही अलग-अलग माने जाएंगे।

(d) कठोरों के निर्धारण में समानता :-

कठोरों का निर्धारण कठोर समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कठोरों का काम सभी के उपर डाला जाए। इस प्रयोग में कठोर देने की समानता के आधार पर भेद दिया जा सकता है।

(e) विवेकपूर्ण आधार पर भेदभाव मान्य :-

कानूनी समानता का विचार राज्य द्वारा मनमाने आधार पर दिए जानेवाले भेदभाव को ही निषेध करता है। विवेकपूर्ण आधार पर यदि किसी को विशेष को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो समानता का सिद्धांत का निषेध नहीं करता, बल्कि कि उस स्थिति में उस को के सब लोगों पर वे समान रूप से लागू हों।

2. राष्ट्रपतीय समानता

राष्ट्रपतीय समानता से हमारा तात्पर्य राष्ट्रपतीय अधिकार के माध्यम पर सभी को समान पहुँच से है। सभी नागरिकों के पास समान राष्ट्रपतीय अधिकार होने चाहिए। सरकार के काम करने में उनकी समान आवाज होनी चाहिए और उन्हें देश के राष्ट्रपतीय जीवन और मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के समान अवसर होने चाहिए।

राष्ट्रपतीय समानता के अंतर्गत सामान्य रूप से निम्नलिखित समानताएं काम में हैं -

(a) मतदान का अधिकार :-

इसके अंतर्गत सभी धर्म, जाति, संपत्ति, शिक्षा एवं लिंग के आधार पर किसी भेद-भाव